



The University of Patanjali Act, 2006

Act 4 of 2006

Keyword(s):

Academic Council, Chancellor, Constituent College, Council for Technical Education, Distance Education System, Faculty, Hall, Teacher, UGC, University, Indian Medical Central Council

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 05 अप्रैल, 2006 ई0

चैत्र 15, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 717/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006

देहरादून, 05 अप्रैल, 2006

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित पतंजलि विश्वविद्यालय, 2006 पर दिनांक 05 अप्रैल, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 04, सन् 2006 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006

(अधिनियम सं0 04, वर्ष 2006)

राज्य में भारतीय प्राचीन संस्कृति एवं वैदिक विज्ञान आधारित योग, आयुर्वेद एवं अन्य कृषि जड़ी-बूटीकरण के क्षेत्र में गहन शिक्षण-प्रशिक्षण एवं शोधकार्य आदि की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में न्यास/ट्रस्ट अधिनियम के अधीन पंजीकृत पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा प्रायोजित “पतंजलि विश्वविद्यालय” नामक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसे निगमित करने एवं उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने हेतु यह

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय - 1

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 है।
 (2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएँ

2. (1) जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में
- (क) 'विद्या परिषद' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद से है,
 - (ख) व्यवस्थापक मण्डल का तात्पर्य विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल से है;
 - (ग) 'कुलाधिपति' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;
 - (घ) घटक महाविद्यालय का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, या संस्था से है;
 - (ङ) 'तकनीकी शिक्षा परिषद' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;
 - (च) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण (टेलीकॉस्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, अन्य पारस्परिक विधियाँ, ई-मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई-लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम, या ऐसे किसी वीडियो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;
 - (छ) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं;
 - (ज) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की संकाय से है;
 - (झ) 'वित्त समिति' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;
 - (ञ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;
 - (ट) 'हाल' अथवा छात्रनिवास का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई से है;
 - (ठ) 'विहित' का तात्पर्य परिणियमों द्वारा विहित से है;

- (ड) किसी संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य का तात्पर्य संघटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसमें जहां प्राचार्य नहीं है, उप-प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;
- (ढ) 'कुल सचिव' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है;
- (ण) क्षेत्रीय 'केन्द्र' का तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से किया गया हो;
- (त) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;
- (थ) 'परिनियमों और नियमावली' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और नियमावलियों से है;
- (द) 'अध्ययन' केन्द्र का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो;
- (ध) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिससे विश्वविद्यालय या किसी संगठक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानवण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी संगठक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है;
- (न) 'विश्वविद्यालय' अनुदान आयोग' का तात्पर्य उस संस्थान से है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गयी है;
- (प) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित पतंजलि विश्वविद्यालय से है;
- (फ) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है।
- (ब) "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्" से तात्पर्य भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन स्थापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से है।

अध्याय - 2

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

3. (1) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा। लिए प्रस्ताव

- (2) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगी। इस आवेदन-पत्र के प्रस्ताव में निम्न विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे:-
- (क) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) का पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य
- (ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;
- (ग) आगामी पांच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार;
- (घ) संकायों की प्रकृति, पाठ्यक्रम तथा आरम्भ किया जाने वाला प्रस्तावित शोध कार्य;
- (च) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे-भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख-सुविधायें;
- (छ) आगामी पांच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिचय;
- (ज) मंदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय;
- (झ) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;
- (ट) आन्तरिक संसाधनों-विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं अन्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;
- (ठ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाले रियायतों या छूटों की सीमा निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेश से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न वरों पर, यदि कोई हों, लिये जाने वाली शुल्कों के स्वरूप का ध्यौरा;
- (ड) पतंजलि योगपीठ में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन
- (ढ) विश्वविद्यालय में छात्रों की चयन पद्धति,
- (त) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति प्रवेश सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति।

- विश्वविद्यालय की स्थापना 4. (1) यदि राज्य सरकार आवश्यक ऐसी जांच करने के उपरान्त जिसे वह आवश्यक समझे, का समाधान हो जाये कि धारा 3 की उपधारा (2) की निर्विष्ट शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं तो पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) विल्ली, सम्पर्क कार्यालय- कृपालु बाग आश्रम, कनखल, हरिद्वार (उत्तरांचल) को स्थायी धिन्यास निधि स्थापित करने के लिए निर्देश देगी;
- (2) स्थायी धिन्यास निधि की स्थापना के उपरान्त राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर प्रमाण-पत्र निर्गत करेगी।

- (3) पतंजलि विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तरांचल हरिद्वार, में स्थित होगा तथा जैसा समय-समय पर वह अपनी अधिकारता के अन्वय अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं योग प्रशिक्षण केन्द्रों, अनुसंधान संस्थान आदि की स्थापना कर सकेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना होगा।
- (4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यवस्थापक मंडल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुए निगमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद चलाया जा सकता है।
- (5) उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहीत निर्मित, सृजित, व्यवस्थित अथवा निर्मित भूमि, चल एवं अचल सम्पत्तियां भी लिए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) एवं दिव्य योग मन्दिर (ट्रस्ट) की सम्पत्तियों को छोड़कर विश्वविद्यालय को अन्तरति एवं उसमें निहित हो जायेगी।
- (6) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उन्हें अधिग्रहीत किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा।

5. विश्वविद्यालय स्वतः वित्त पोषक होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता, अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई मांग करेगा, और न ही उसके लिए हकदार होगा।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र एवं योग प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र हो सकते हैं पतंजलि विश्वविद्यालय अन्य अनुसंधान संस्थान व अन्य विश्वविद्यालय के साथ सामूहिक अनुसंधान कार्य आदि कर सकता है। किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी। परिसर के बाहर केन्द्र या अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय मानको की स्थापना और उनके अनुरक्षण सम्बन्धी) विनियम का भी पालन किया जाना होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

7. (1) जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी वे निम्नलिखित हैं:-

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(क) पतंजलि विश्वविद्यालय का उद्देश्य प्राचीन ऋषि-महर्षियों द्वारा निर्दिष्ट मौलिक तत्व ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में व्यापक अध्ययन-शिक्षण एवं गहन शोध अनुसंधान का सुव्यवस्थित तथा विश्व स्तर की विद्या को स्थापित करना है।

- (ख) राष्ट्रधर्म, स्वदेश प्रेम, स्वदेशी खानपान, आहार-शुचिता, जड़ी-बूटी व आयुर्वेद के संरक्षण व संवर्द्धन के विषय में युवाओं को जागृत करके रोजगारपरक शिक्षा को उपलब्ध कराना।
- (ग) योग, आयुर्वेद सहित वेद-वेदांग आदि सभी प्राचीन विधाओं पर आधारित विविध महाविद्यालयों की स्थापना एवं पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करना। विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु नये अन्य डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आरम्भ करने का अधिकार होगा।
- (घ) उपरोक्त (ग) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए अनवरत शिक्षा के अधीन संघटक केन्द्र की स्थापना।
- (2) भारतीय संस्कृति योग, आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना और उसके द्वारा :-
- (क) ज्ञान की ऐसी सम्बन्धित शाखाओं में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जिन्हें वह आवश्यक समझे;
- (ख) विद्यालयों में ज्ञान की उत्पत्ति, और प्रचार के लिए शोध कार्य की व्यवस्था करना जिससे विश्व पटल पर इन विधाओं को स्थापित किया जा सके तथा छात्र/छात्राओं को रोजगार भी सहज उपलब्ध हो सके।
- (ग) योग, आयुर्वेद सम्बन्धी अध्ययन और ऐसी अन्य गतिविधियां आरम्भ करना जिससे आम जनता को योग, आयुर्वेद का लाभ मिल सके जिससे रोगमुक्त स्वस्थ एवं समृद्ध समाज व राष्ट्र की सोच को विकसित किया जा सके।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

8. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी; अर्थात्
- (क) भारतीय संस्कृति, मानविकी, सूचना प्रौद्योगिकी, सहस्रबद्ध क्षेत्रों तथा सम्बन्धित सभी विषयों में शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्द्धन और प्रसार का प्राविधान करना;
- (ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियां सम्पादित करना जो आवश्यक अथवा साध्य हों;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने :-
- (1) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या योग प्रशिक्षण केन्द्रों में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या
- (2) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो।

- (घ) परिनियमों/प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानव् उपाधियों, या अन्य शैक्षिक विशेषताएं प्रदान करना;
- (ङ) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना।
- (च) ऐसी फीस, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किया जाये;
- (छ) धारा (7) में उल्लेखित योग, आयुर्वेद और अन्य क्षेत्र में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;
- (ज) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त (पाठ्येत्तर) अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना;
- (झ) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा योग प्रशिक्षण केन्द्रों में संकाय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;
- (ञ) पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और योग प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रयोजनार्थ संदान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण धारण, अनुरक्षण और निपटारा करना;
- (ट) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए हाल/छात्रावास आदि स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;
- (ठ) आवास का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना;
- (ड) प्रशासनिक, प्रबन्धन एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सुजन;
- (ढ) अन्य विश्वविद्यालय से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें;
- (ण) वृरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार वृरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;
- (त) अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;

- (थ) विश्वविद्यालय या किसी संगठक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और योग प्रशिक्षण केन्द्रों में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;
- (द) विश्वविद्यालय या किसी संगठक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, और योग प्रशिक्षण केन्द्रों में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तरांचल राज्य के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था करना;
- (ध) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे अन्य सभी कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हो या न हों;
- (न) योग आयुर्वेद तथा सम्बन्धित विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना तथा डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र आदि के लिए पाठ्यक्रम आरम्भ करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा आच्छादित हो परन्तु डिप्लोमा सर्टिफिकेट आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम लागू करने हेतु विश्वविद्यालय को स्वतन्त्रता होगी।
- (प) फिल्म कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सी.डी., वी.सी.डी. और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;
- (फ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त करना;
- (ब) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना;
- (भ) संविदा करना उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना।
- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी लेकिन उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों में शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और योग प्रशिक्षण केन्द्रों को चाहे उन्हें

विशेषाधिकार स्वीकृत हो अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्था को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो संविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा :-

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने पर प्रतिबन्ध है। परन्तु और यह भी इस धारा के किसी बात के होते हुए भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्यायन केन्द्रों या योग-प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

अध्याय - 3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

विश्वविद्यालय के अधिकारी

- (क.) कुलाध्यक्ष (विजिटर)
- (ख.) कुलाधिपति
- (ग.) कुलपति
- (घ.) प्रति-कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर)
- (च.) सहायक कुलाध्यक्ष
- (छ.) कुल सचिव
- (ज.) वित्त अधिकारी और
- (झ.) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाय।

12. (1) उत्तरांचल के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

कुलाध्यक्ष (विजिटर)

- (2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियों एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

- (3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात:-

(क) विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मंगाना;

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर यदि कुलाध्यक्ष उसका समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय,

अधिनियम, विनियम, अध्यादेश अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें, निर्देश दे सकेंगे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

- (4) मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन होगा।

कुलाधिपति

13. (1) योगब्रह्मि स्वामी रामदेव अध्यक्ष पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) एवं दिव्य योग मन्दिर (ट्रस्ट) कनखल, हरिद्वार इस पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे, जिनका कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा तत्पश्चात् पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) अपने ही ट्रस्टियों में से कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से कुलाधिपति नियुक्त करेगी।
- (2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ होंगी जो उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जाय।

कुलपति

14. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति को नियुक्ति की जायेगी।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-
- (क) कुलाध्यक्ष तथा कुलाधिपति द्वारा नामित एक-एक सदस्य;
- (ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;
- (ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मनोनीत तीन सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।
- (3) समिति योग्यता के आधार पर उप कुलाधिपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेज देगी।
- (4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।
- (5) जहाँ अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के

किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।

- (6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।
- (7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के बाद कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

15. प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जाये और प्रति-कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

प्रति-कुलपति

16. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

संकायाध्यक्ष

17. (1) कुल सचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी, जैसे कि विहित की जाए।

कुल सचिव

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

18. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जायें।

वित्त अधिकारी

19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें, तथा शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

अन्य अधिकारी गण

अध्याय - 4

विश्वविद्यालय प्राधिकरण

- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी 20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-
- (क) व्यवस्थापक मण्डल
 - (ख) प्रबन्धक मण्डल
 - (ग) शैक्षिक (विद्या) परिषद
 - (घ) वित्त समिति, और
 - (च) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किये जाएँ।
- व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियाँ 21. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे
- (क) कुलाधिपति - अध्यक्ष
 - (ख) कुलपति - सवस्य-सचिव
 - (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार का सचिव
 - (घ) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार का सचिव
 - (च) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा नामित पांच सवस्य
 - (छ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित तीन शिक्षा विद्
 - (ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक सदस्य
 - (झ) योग, आयुर्वेद के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वाले संस्थान के वैज्ञानिक या अधिकारी में से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन अधिकारी।
- (2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :-
- (क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण
 - (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे ऐसे अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो का पुनर्विलोकन;
 - (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;
 - (घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन;
 - (च) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;
 - (छ) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों को अनुमोदन; और

- (ज) ऐसे निर्णय एवं प्रयास करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं।
- (झ) एक या अधिक पर्यवेक्षक नामित करना जो कि समय-समय पर कुलाधिपति की सलाह एवं निर्देशों के अन्तर्गत नीति एवं ढांचा निर्धारित करेगा/करेंगे, जिसके अन्तर्गत प्रबन्धक मण्डल, विद्या परिषद, वित्त समिति एवं अन्य ऐसे प्राधिकरण जो कि परिनियमों द्वारा घोषित हों, विश्वविद्यालय के उचित प्रशासन के लिए कार्य करेंगे एवं प्रस्ताव करेंगे।
- (3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी जैसा कि कुलाधिपति उचित समझे।

22. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

प्रबन्ध मण्डल

- (क) कुलपति;
- (ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी;
- (ग) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा नामित पांच सदस्य;
- (घ) एक वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक;
- (च) कुलाधिपति द्वारा नामित दो संकायाध्यक्ष
- (छ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न पद का न हो।

कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति एवं कुल सचिव इसके सचिव होंगे।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जायें।

23. (1) शैक्षिक (विद्या) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

शैक्षिक (विद्या) परिषद

- (क) कुलपति - सभापति
- (ख) कुल सचिव - सचिव;
- (ग) ऐसे अन्य सदस्य - जैसा परिनियमों के विहित किया जाये।

(2) शैक्षिक (विद्या) परिषद, विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

24. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

वित्त समिति

- (क) कुलपति - सभापति;
- (ख) वित्त अधिकारी;

- (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम न हो;
- (घ) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम न हो;
- (च) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जायें।
- (2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देख-भाल करेगी, और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्यक्षीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकरण

25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण
कार्यवाही का
अविधिमान्य न होना

26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय - 5

परिनियम और नियमावली

परिनियम

27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत है :-
- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य-सम्पादन और ऐसी इकाइयों के गठन की प्रक्रिया जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है;
- (ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;
- (ग) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें, तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य;
- (घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा शर्तें
- (च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;
- (छ) विभागों और संकायों का सृजन, उत्सादन और उसकी पुनर्संरचना;

- (ज) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;
- (झ) मानव् उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;
- (ट) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबन्ध
- (ठ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की, जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है तथा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के लिए स्थानों के आरक्षण की प्रक्रिया;
- (ड) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क
- (ढ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, फीस माफी, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना;
- (त) पदों का सृजन और समापन की प्रक्रिया;
- (थ) अन्य मामले जो विहित किये जायें।

28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये परिनियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।
- (2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

29. व्यवस्थापक मंडल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

परिनियम संशोधन करने की शक्ति नियम

30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए, नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपलब्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :-
- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;
 - (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;
 - (ग) उपाधियों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;
 - (घ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
 - (च) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;
 - (छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं में प्रवेश करने के लिए लिया जाने वाला शुल्क;

- (ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;
- (झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;
- (ट) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्रावधान किया जाये।

नियमावली
कैसे बनायी
जायेगी

31. (1) नियमावली व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी जायेगी और इस प्रकार बनायी गई नियमावली राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जो कि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से 2 माह के अन्दर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के साथ अपना अनुमोदन दे सकेगी।
- (2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमावली के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय करने में असमर्थ रहती है वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।

नियमावली को
संशोधित करने
की शक्ति

32. राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्वधीन रहते हुए और प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से शैक्षिक (विद्या) परिषद् नये तथा अतिरिक्त नियम बना सकेगी या नियमावली को संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

- कर्मचारियों की सेवा शर्तें 33. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।
- (2) छात्रों या कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विश्वविद्यालय परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम (आर्बिट्रेशन) अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध मंडल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।
- (4) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (5) अधिकरण के कार्यों को विनियमित करने की प्रक्रिया इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विहित की जाये।

34. विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अपील का अधिकार योग प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, योग प्रशिक्षण केन्द्र के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।
35. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायें, ऐसे भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जैसा वह उचित समझे।
36. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय का सदस्य के रूप में विधिवत् निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
37. जब भी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई हो, वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई, समस्त सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों यदि कोई हो, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।
38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता है।
39. कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई, किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सम्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।
40. इस अधिनियम और परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी :-
- (क) प्रथम कुलपति एवं प्रति-कुलपति (प्रो.-वाइस चांसलर), यदि कोई है, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर कार्य करेगा;
- (ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी जो तीन वर्ष की अवधि तक उस पद कार्य करेंगे;
- (ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा;
- (घ) प्रथम प्रबन्धक मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।

भविष्य निधियां एवं पेंशन

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद सामांत्यां का गठन

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

सम्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

संक्रमणकालीन उपबन्ध

- स्थायी विन्यास निधि 41. (1) विश्वविद्यालय द्वारा कम से कम तीन करोड़ रुपये स्थायी विन्यास निधि स्थापित की जायेगी जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर स्वमेव ही बढ़ा सकेगा, परन्तु घटा नहीं सकता;
- (2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को विहित रीति से निवेश करने की शक्ति होगी;
- (3) विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य निधि या विकास निधि से कोई भी धनराशि स्थायी विन्यास निधि में अन्तरित की जा सकती है। विश्वविद्यालय के समापन के अतिरिक्त किसी भी अन्य परिस्थिति में अन्य प्रयोजनों के लिए कोई धनराशि विन्यास निधि की राशि से अन्तरित नहीं की जा सकती;
- (4) स्थायी विन्यास निधि की राशि से प्राप्त आय का 75 प्रतिशत से अधिक विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जायेगा और शेष 25 प्रतिशत को स्थायी विन्यास निधि में पुनर्निवेशित कर दिया जायेगा।
- सामान्य निधि 42. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :-
- (क) विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाली सभी शुल्क;
- (ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
- (ग) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा किये गये सभी अंशदान और
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।
- (2) सामान्य निधि हेतु आशयित निधि का प्रयोग वि.वि. के सभी आवर्तक व्ययों की पूर्ति के लिए किया जायेगा।
- विकास निधि 43. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेगी, अर्थात्:-
- (क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;
- (ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि
- (ग) पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा किये गये सभी अंशदान
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान और
- (च) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।
- (2) समय-समय पर विकास निधि में जमा की गयी निधियों का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।
- निधि का अनुरक्षण 44. धारा 41, 42 और 43 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

45. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। वार्षिक प्रतिवेदन
- (2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।
- (3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।
46. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्धक मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी। लेखा व लेखा परीक्षा
- (2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रति वर्ष लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जायेगी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आई.सी.ए.आई.) के सदस्य हों।
- (3) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र की एक प्रति प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखों, तुलन-पत्र और लेखा-परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रति वर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
- (5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखा-परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा किये गये निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।
47. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से विधिवत् रखी गई किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्टि होने के प्रथम वृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संख्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी। विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति
48. (1) यदि पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके समापन का प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा। विश्वविद्यालय का विघटन
- (2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कूप्रबन्ध, कूप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाइयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसी विहित की जाये, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

- (3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा जो इस विषय राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, परन्तु उसके लिए पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) कारण बताओ नोटिस के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ऐसी कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की जायेगी।
- (4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं तत्सम्बन्धी सवैधानिक संस्था से परामर्श करके पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा विश्वविद्यालय के प्रस्तावित चिनांक से, और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अंतिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्व-विद्यालय के व्यय

49. (1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिये होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।
- (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्धन ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

प्रवेश तथा शुल्क के लिए पारित विधि का लागू होना

50. निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं शुल्क के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जो विधि पारित की जायेगी वह इस विश्वविद्यालय में भी लागू होगी।

कठिनाईयों का निराकरण

51. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो; प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिनियम या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति की पश्चात् नहीं दिया जायेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

यू० सी० ध्यानी,
सचिव।

No.717/Vidhayee & Sansadiya Karya/2006

Dated Dehradun, April 05, 2006

NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the University of Patanjali Bill, 2006 (Uttaranchal-Adhiniyam Sankhya 04 of 2006).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 05-04-2006.

THE UNIVERSITY OF PATANJALI ACT, 2006

(THE UTTARANCHAL ACT No. 04 OF 2006)

To establish and incorporate an University in the name of University of Patanjali with facilities for education, training and research in the areas of Yoga, Ayurveda and culture of Medicinal Herbs/Plants and studies and in related areas sponsored by The Patanjali Yog Peeth (Trust).

AN

ACT

IT IS HEREBY enacted by the Uttaranchal State Assembly in the 57th Year of the Republic of India as follows :

CHAPTER-I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the University of Patanjali Act, 2006.

Short title and
Commencement

(2) It shall come into force on the date, the Notification is issued by the State Government.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires:-

Definitions

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Board of Governors" means the Board of Governors of the University;

(c) "Chancellor" means the Chancellor of the University;

(d) "Constituent College" means a college or institution maintained by the University;

(e) "Council for Technical Education" means the All India Council for Technical Education established under section (3) of the All India Council for Technical Education Act, 1987;

(f) "Distance Education System" means the system of imparting education through any means of information technology and communication such as broadcasting, telecasting, correspondence course, seminar, contact program or a combination of any two or more such means;

(g) "Employee" means employee appointed by the University and includes teachers and other staff of the University or a constituent college;

(h) "Faculty" means faculty of the University;

- (i) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
- (j) "Government" means the Government of Uttaranchal;
- (k) "Hall" means a unit of residence for students maintained or recognized by the university or a contentment college,
- (l) "Prescribed" means prescribed by the Statutes;
- (m) "Principal" in relation to a constituent college, means the head of the constituent college, and includes, where there is no Principal, the Vice Principal or any other person for the time being appointed to act as Principal;
- (n) "Registrar" means the Registrar of the University;
- (o) "Regional Centre" means a centre established or maintained by the University for the purpose of co-ordination and supervising the work of Study Centres in any region and for performing such other functions as may be conferred on such centre by the Board of Management;
- (p) "State" means State of Uttaranchal;
- (q) "Statutes" and "Rules" mean, respectively, the Statutes and Rules of the University;
- (r) "Study Centre" means a centre established, maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students;
- (s) "Teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor/ Lecturer or such other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a Constituent College and includes the Principal of Constituent College;
- (t) "UGC" means University Grants Commission established under The University Grants Commission Act, 1956;
- (u) "University" means the university of Patanjali established under this Act.
- (v) "Visitor" means the visitor of the University.
- (w) "Indian Madical Central Council" means the Indian Madical Central Council established under The Indian Madical Central Council Act, 1970;

CHAPTER-II

The University and its Objects

Proposal for 3.
the establishment
of the University

- (1) The Patanjali Yog Peeth (Trust), N. Delhi shall have the right to establish the University in accordance with the provisions of this Act.
- (2) An application containing the proposal to establish a University shall be made to the State Government by the Patanjali Yog Peeth (Trust). The proposal shall contain the following particulars, namely:-
 - (a) the objects of the University along with the details of the Patanjali Yog Peeth (Trust),
 - (b) the extent and status of the University and the availability of land;

- (c) the nature and type of programmes of study and research to be undertaken in the University during a period of the next five years;
- (d) the nature of faculties, course of study and research proposed to be started;
- (e) the campus development such as buildings, equipment and structural amenities;
- (f) the phased outlays of capital expenditure for a period of the next five years;
- (g) the item-wise recurring expenditure, sources of finance and estimated expenditure for each student;
- (h) the scheme for mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayments to each source;
- (i) the scheme of generation of funds internally through the recovery of fee from students, revenues anticipated from consultancy and other activities relating to the objects of the University and other anticipated incomes;
- (j) the details of expenditure on unit cost, the extent of concessions or rebates in fee freeship and scholarship for students belonging to economically weaker sections and the fee structure indicating varying rate of fee, if any, that would be levied on non resident Indians and students of other nationalities;
- (k) the years of experience and expertise in the concerned discipline at the command of the Patanjali Yoga Peeth (Trust) as well as the financial resources;
- (l) the system for selection of students to the courses of study at the University, and
- (m) status of fulfillment of such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.

4. (1) Where the State Government, after such inquiry as it may deem necessary, is satisfied that Patanjali Yog Peeth (Trust), Delhi camp office at Kripalu Bagh Ashram, Kankhal, Hardwar has fulfilled the conditions specified in sub-section (2) of Section 3, it may direct the Patanjali Yog Peeth (Trust) to establish an Endowment Fund.

Establishment
of University

- (2) After the establishment of the Endowment Fund, the State Government may, by notification in the Official Gazette, accord sanction for establishment of the University.

- (3) The Patanjali University shall be located at Hardwar, Uttaranchal and it may also have campuses or regional centres, Study Centres and Career Academic Centres at such other places, as may be specified by it from time to time. provided that the procedure established by University Grant Commission & other Constitutional bodies shall be complied.
- (4) The Chancellor, the Vice-Chancellor, members of the Board of Governors, members of the Board of Management and the Academic Council for the time being holding office as such in the University so established, shall constitute a body corporate and can sue and be sued in the name of the University.
- (5) On the establishment of the University under sub-section (2), the land and other movable and immovable properties acquired, created, arranged or built by the University for the purpose of the University except the properties of Patanjali Yog Peeth and Divya Yog Mandir (Trust), shall stand transferred to, and vest in, the University.
- (6) The land, building and other properties acquired for the University shall not be used for any purpose, other than that for which the same is acquired.
- University not to be entitled to financial assistance 5. The University shall be self-financing and shall neither make a demand nor shall be entitled to any grant in-aid or any other financial assistance from the State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government.
- No Power to affiliate any institute. 6. The University may have Constituent Colleges, Regional Centres, Study Centres and Yoga training and research Centres, but shall have no power to admit any other college or institution to the privileges of affiliation. Patanjali University may carryout the research activities in conjunction with other research institutes & Universities. The provisions of the regulation of University Grant Commission (Establishment and maintenance of standard in Private Universities) shall have to be complied with in relation to the establishment the off campus centres or study centres.
- Objects of the University 7. (1) The objectives for which the University is established are as follows:-
 (a) objective of Patanjali University is to establish and investigate thorough scientific basis for the knowledge advanced by the ancient Indian sages and to undertake systematic research investigations in the background of scientific facts so as to provide it a firm foundation in the emerging world;
 (b) to provide employment oriented education and awaking to the youths so that they become in grained to preserve knowledge of Ayurveda, herbal medicines, food hygiene, Rashtra dharma, Swadesh prem and swadeshi life style;
 (c) to establish various colleges and institutions based on traditional lines including Yog, Ayurveds, Veda and Vedang etc. and to provide graduate and post graduate degree courses. And will have right to meet our own objectives, to run diploma courses and certificate programmes which may be sponsored by University Grants Commission;

(d) to establish constituent centre for continuing Education to provide instructions through distance learning methodology for the courses in (c) above.

(2) To establish an R & D center to promote research and innovations in the field of Yog, Ayurveda, Indian culture and Traditional Sciences.

- (a) to provide for instructions and training in such related branches of learning as it may deem fit.
- (b) to arrange the research activities for the creation and dissemination of knowledge in schools, so that these traditions may be establish on the world fora & also for the easy achievements of employment of students.
- (c) to undertake Yoga/Ayurveda and other such activities related studies so that common people leading to Revival of Indian culture in high esteem.

8. (1) The University shall have the following powers, namely :-

Power of the University

- (a) to provide for instruction in all disciplines of Indian culture, Humanities information technology and allied fields and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;
- (b) to carry out all such activities as may be necessary or feasible in furtherance of the objects of the University;
- (c) to hold examinations for, and to institute grants and confer degrees or other academic distinctions to, and on, persons, who-
 - (i) have pursued a course of study in the University or in a constituent College or through its distance education system at Regional Center/ Study Center/ Yoga Training Centres
 - (ii) have carried on research in the University or in a constituent body or under its distance education system.
- (d) to confer honorary degree or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes/ Provisions;
- (e) to institute and award fellowships, scholarships and prizes etc. in accordance with the Statutes;
- (f) to demand and receive such fees, bills, invoices and collect charges as may be fixed by the Statutes or rules, as the case may be;
- (g) to make provisions for the advancement of Yoga and Ayurveda and other mentioned in Section 7;
- (h) to make provisions for extra curricular activities for students and employers;
- (i) to make appointments of faculty, officers and employees of the University or a Constituent College, Regional Center, Study Center and Yoga Training Center;

is,
d
is,
i by

- (j) to receive donations and gifts of any kind and to acquire, hold, manage, maintain and dispose of any movable or immovable property, including trust and endowment properties for the purpose of the University or a Constituent College, Regional Center, Study Center and Yog training Centers with the prior permission of Patanjali Yog Peeth (Trust).
- (k) to institute and maintain halls and to recognize places of residence for students of the University or in a Constituent College;
- (l) to supervise and control the residence, and to regulate the discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees, including their Code of Conduct;
- (m) to create administrative, managerial, employees and other necessary posts;
- (n) to co-operate or collaborate with other Universities in such manner and for such purposes as the University may determine from time to time;
- (o) to provide distance education system and the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organized;
- (p) to organize and conduct refresher courses, orientation courses, workshops, seminars and other programs for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff;
- (q) to determine standards of admission to the University or a Constituent College, Regional Center, Study Center and Yoga training Center through specialized committee with the approval of Academic Council;
- (r) to make special provision for students belonging to the state of Uttaranchal for admission in any course of the University or in a Constituent College, Regional Center, Study Center and Yoga training Center;
- (s) to do all such other acts or things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the objects of the University;
- (t) to prescribe such courses for Bachelor Degree, Post Graduate and Research and to start diplomas, certificates etc. in Yog and Ayurveda related subjects; which would be covered by UGC & AICTE but university shall have right to start diplomas Certificates etc. in its own subject.
- (u) to provide for the preparation of instructional materials, including films, cassettes, tapes, CD, VCD and other softwares;
- (v) to recognize examinations of, or periods of study (whether in full or in part) at, other universities, institutions or other places of higher learning as equivalent to examinations or periods of study in the University and to withdraw such recognition at any time;
- (w) to raise, collect, subscribe and borrow with the approval of the Governing Body whether on the security of the University, money for the purpose of the University;
- (x) to enter into, carry out, vary or cancel contracts.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, but without prejudice to the provisions of sub-section (1), it shall be the duty of the University to take all such steps as it may deem fit for the promotion of the open university and distance education systems, and for the determination of standards of teaching evaluation and research in such systems and for the purpose of performing this function, the University shall have such powers, including the power to allocate and disburse grants to Colleges, Regional Centers and Study Centers whether admitted to its privileges or not, or to any other University or institution of higher learning, as may be specified by the Statutes.

9. The University shall be open to all persons irrespective of class, creed or gender:-

University
Open to
all classes,
castes, creed and
gender

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission to students of the State of Uttaranchal. Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University or Constituent Colleges or Regional Centers or Study Centers or, Yog Training Centers to admit in any course of study a larger number of students than may be determined by the Statutes.

10. The University will seek accreditation from the national University accreditation body.

National
Accreditation

CHAPTER-III

Officers of the University

11. The following shall be the officers of the University:-

Officers of the
University

- (a) the Visitor
- (b) the Chancellor;
- (c) the Vice-Chancellor;
- (d) the Pro Vice-Chancellor;
- (e) the Deans of Faculties;
- (f) the Registrar;
- (g) the Finance Officer, and
- (h) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

12. (1) The Governor of Uttaranchal will be the Visitor of the University.
- (2) The Visitor shall, when present, preside at the Convocation of the University for conferring degrees and Diplomas.
- (3) The Visitor shall have the following powers namely :-
 - (a) To call for any paper or information relating to the affairs of the University.
 - (b) on the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any order, proceeding, or decision taken by any authority of the University is not in conformity with the Act, Statutes or Rules, he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied with by all concerned,
- (4) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the approval of the Visitor.

Visitor

- The Chancellor 13. (1) Yog Rishi Swami Ramdev ji, who is President of Patanjali Yog Peeth (Trust) and Divya Yog Mandir (Trust), Kankhal, Hardwar will be the first Chancellor of Patanjali University and will hold office for life long and thereafter Patanjali Yog Peeth (Trust) will appoint Chancellor from among the Trustees with the prior approval of the Visitor.
- (2) The Chancellor shall have other such powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes made there under.
- Vice Chancellor 14. (1) The Vice Chancellor shall be appointed on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes for a term of three years by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).
- (2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following persons, viz, :-
- (a) One person nominated by the Visitor & Chancellor each.
 - (b) The Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Higher Education Department;
 - (c) Three nominees of the Board of Governors, one of whom shall be nominated as the convenor of the committee by the Board of Governors.
 - (3) The committee shall, on the basis of merit, prepare a panel of names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor and forward the same to the Chancellor along with a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each person.
 - (4) The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive and academic Officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.
 - (5) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit with the prior approval of the Chancellor.
 - (6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be laid down by the Statutes of the Rules.
 - (7) The Chancellor is empowered to remove the Vice-Chancellor after due enquiry. It will be open to the Chancellor to suspend the Vice-Chancellor during enquiry depending upon the seriousness of the charges, as he may deem fit.
- The Pro-Vice Chancellor 15. A Pro Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor with prior approval of the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.
- Deans of Faculties 16. Deans of faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.

17. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed. The Registrar
(2) All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University.
(3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required from time to time, by the Chancellor or the Vice-Chancellor.
- (4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other authority, all such information and documents as may be necessary for transaction of their business.
18. The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed. The Finance Officer
19. The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed. Other Officers

CHAPTER-IV

Authorities of the University

20. The following shall be the authorities of the University, namely:- Authorities of the University
- (a) The Board of Governors;
(b) The Board of Management;
(c) The Academic Council;
(d) The Finance Committee; and
(e) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.
21. (1) The Board of Governors shall consists of: The Board of Governors and its powers
(a) The Chancellor -Chairman;
(b) The Vice-Chancellor - Member-Secretary;
(c) Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Higher Education Department or a Secretary to the State Government nominated by the State Government;
(d) Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Medical Education Department or a Secretary to the State Government nominated by the State Government;
(e) Five persons nominated by the Patanjali Yog Peeth (Trust).
(f) Three academicians nominated by the Visitor.
(g) A Nominee of University Grants Commission.
(h) Three Nominees of Officers or Scientist working in the field of Yog and Ayurved nominated by the Chancellor.

(2). The Board of Governors shall be the principal governing body of the University and shall have the following powers, namely:-

- (a) to lay down policies to be pursued by the University;
- (b) to review decisions of the other authorities of the University if they are not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes or the Rules;
- (c) to approve the budget and annual report of the University;
- (d) to make new or additional Statutes or amend or repeal the earlier Statutes and Rules;
- (e) to take decision about voluntary winding up of the University;
- (f) to approve proposals for submission to the State Government; and
- (g) to take such decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objects of the University.
- (h) to nominate an observer or observers who will, time to time, under the advice and directions of the Chancellor decide the policy and frame work within which the Board of Management, Academic Council, Finance Committee and such other authorities as may be declared in the statutes, will function and pass resolutions for the proper administration of the University.

(3) The Board of Governors shall meet at least three times in a year at such time and place as the Chancellor thinks fit.

The Board of Management

22. (1) The Board of Management shall consist of:-

- (a) The Vice-Chancellor;
- (b) A Nominee of Patanjali Yog Peeth (Trust) nominated by the Chancellor.
- (c) Five persons, nominated by the Patanjali Yog Peeth (Trust).
- (d) Two Professors of the University, by rotation on the basis of seniority for a period of one year;
- (e) Two Deans of the faculties as nominated by the Chancellor;
- (f) Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Higher Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government. The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management and the Registrar shall be the Secretary of the Board of Management.

(2) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed.

The Academic Council

23. (1) The Academic Council shall consist of:-

- (a) the Vice-Chancellor - Chairman;
- (b) the Registrar - Secretary;
- (c) such other members as may be prescribed in the Statutes.

(2) The Academic Council shall be the Principal Academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Rules, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

The Finance Committee

24. (1) The Finance Committee shall consist of:-

- (a) the Vice-Chancellor - Chairman;
- (b) the Finance Officer
- (c) Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Higher Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government;
- (d) Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Medical Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government;
- (e) such other members as may be prescribed in the Statutes.

- (2) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of financial matters and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes and Rules, co-ordinate and exercise general supervision over the financial matters of the University.

Other Authorities 25. The constitution, powers and functions of the authorities of the University shall be such as may be prescribed.

Proceedings not invalidated on account of vacancy 26. No act or proceeding of any authority of the University shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the authority.

CHAPTER-V

Statutes and Rules

Statutes 27. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and staff, as given below:-

- (a) the procedure for transaction of business of the Authorities of the University and the composition of bodies not specified in this Act;
- (b) the operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund;
- (c) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor, the Registrar and the Finance Officer and their powers and functions;
- (d) the mode of recruitment and the conditions of service of the other officers, teachers and employees of the University;
- (e) the procedure for resolving disputes between the University and its Officers, faculty members, employees and students;
- (f) creation, abolition or restructuring of department and faculties;
- (g) the manner of co-operation with other Universities or Institutions of higher learning.
- (h) the procedure for conferment of honorary degrees;
- (i) provisions regarding grant of freeships and scholarships;
- (j) number of seats in different courses of studies and the procedure of admission of students to such courses including reservation of seats for Uttaranchal Students;
- (k) the fee chargeable from students for various courses of studies;
- (l) institution of fellowships, scholarships, studentships, freeships, medals and prizes;
- (m) procedure for creation and abolition of posts;
- (n) other matter which may be prescribed.

Statutes made 28. (1) The first Statutes framed by the Board of Governors shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within three months from the date of receipt of the Statutes give its approval with or without modification.

(2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the Statutes within the period specified under Sub-section (1) it shall be deemed to have approved by the State Government.

Power to amend the Statutes 29. The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government, make new or additional Statutes or amend or repeal the existing Statutes.

Rules 30. Subject to the provisions of this Act, the Rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;
- (b) the course of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;
- (c) the award of degrees and other academic distinctions;
- (d) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (e) the conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;
- (f) the fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University;
- (g) the conditions of residence of the students at the University or a constituent college;
- (h) maintenance of discipline among the students of the University or a constituent college;
- (i) all other matters as may be provided in the Statutes and Rules under the Act.

- Rules how made 31. (1) The rules shall be made by the Board of Governors and the rules so made shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within two months from the date of receipt of the rules, give its approval with or without modification.
- (2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the rules within the period specified under sub-section (1), it shall be deemed to have been approved by the State Government.

Power to amend Rules 32. The Board of Governors may, with the approval of the State Government make new or additional rules or amend or repeal the rules.

CHAPTER-VI

Miselleneous

Conditions service of employees

33. (1) Every employee shall be appointed under a written contract, which shall be kept in the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.
- (2) Disciplinary action against the students/employees shall be governed by procedure prescribed in the Statutes.
- (3) Any dispute arising out of the contract between the University and an employee shall, at the request of the employee, be referred to a tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor.
- (4) The decision of the tribunal in such matter shall be final.
- (5) The procedure for regulating the work of the tribunal shall be such as may be prescribed.

34. Every employee or student of the University or of a Constituent College, Regional Center, Study Center and Yog Training Centers notwithstanding anything contained in the proposed Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Board of Management against the decision of any officer or authority of the University or of the Principal of any such Constituent College, Regional Center, Study Center and Yog Training Center as the case may be and thereupon the Board of Management may confirm, modify or change the decision appealed against. Right to appeal
35. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. Provident fund & pension.
36. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final. Disputes as to constitution of University authorities and bodies
37. Whenever any authority of the University is given power by this Act or the statutes to appoint committees, such committees, shall, save as otherwise provided, consist of any or all the members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority in each case thinks fit. Constitution of Committees
38. Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members, of any Authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he/ she fills would have been a member. Filling of casual vacancies
39. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the University for anything, which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, the Statutes or the Rules. Protection of action taken in good faith
40. Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act and the Statutes:- Transitional provisions
- (a) the first Vice-Chancellor and Pro Vice-Chancellor, if any shall be appointed by the Chancellor and the said officer shall hold office for a term of three years;
- (b) the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor who shall hold office for a term of three years;
- (c) the first Board of Governors shall hold office for a term not exceeding three years;
- (d) the first Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic Council shall be constituted by the Chancellor for a term of three years.
41. (1) The University shall establish a permanent endowment fund of at least rupees three crores which may be increased suo motu but shall not be decreased. Permanent Endowment Fund
- (2) The University shall have power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.
- (3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund. Excepting the dissolution of the University, in no other circumstances can any monies be transferred from corpus of the endowment fund for other purposes.

- (4) Not exceeding 75% of the incomes received from the corpus permanent endowment fund shall be used for the purposes of development works of the University. The remaining 25% shall be reinvested into the permanent endowment fund.

General Fund 42. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:-
 (a) all fees which may be charged by the University;
 (b) all sums received from any other source;
 (c) all contributions made by the Patanjali Yog Peeth (Trust).
 (d) all contributions/ donations made in this behalf by any other person or body, which are not prohibited by any law for the time being in force.

- (2) The funds credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the University.

Development Fund 43. (1) The University shall also establish a development fund to which the following funds shall be credited, namely:-
 (a) development fees which may be charged from students;
 (b) all sums received from any other source for the purposes of the development of the University;
 (c) all contributions made by the Patanjali Yog Peeth (Trust).
 (d) all contributions/ donations made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force; and
 (e) all incomes received from the permanent endowment fund.

- (2) The funds credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.

Maintenance of fund 44. The funds established under sections 41, 42 and 43 shall, subject to general supervision and control of the Board of Governors, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

Annual Report 45. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be submitted to the Board of Governors for its approval.
 (2) The Board of Governors shall consider the annual report in its meeting and may approve the same with or without modification.
 (3) A copy of the annual report duly approved by the Board of Governors shall be sent to Visitor and the State Government before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.

Accounts and audit 46. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and all funds accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.

- (2) The annual accounts of the University shall be audited by an auditor, who is a member of the Institute of Chartered Accountants of India, every year.
 (3) A copy of the annual accounts and the balance sheet together with the audit report shall be submitted to the Board of Governors well before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.

- (4) The annual accounts; the balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its meeting and the Board of Governors shall forward the same to the Visitor and the State Government along with its observations thereon before the 31st December each year.
- (5) The direction of the State Government on the subject arising out of the accounts and audit report of the University shall be binding on the University.
47. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matter and transaction therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence. Mode of proof of University record
48. (1) If Patanjali Yog Peeth (Trust) proposes dissolution of the Patanjali University in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least three months notice in writing to the State Government. Dissolution of University
- (2) On identification of mismanagement, mal-administration, in-discipline, failure in the accomplishment of the objects of University and economic hardships in the management systems of University, the State Government would issue directions to the management system of University. If the directions are not followed within such time as may be prescribed, the right to take decision for winding up of the University would vest in the State Government.
- (3) The manner of winding up of the University would be such as may be prescribed by the State Government in this behalf. Provided that no such action will be initiated without affording a reasonable opportunity to show cause to the Patanjali Yog Peeth (Trust).
- (4) On receipt of the notice referred to in sub-section (1), the State Government shall, in consultation with the Council for Technical Education and University Grant Commission make such arrangements for administration of the University from date of dissolution of the University by Patanjali Yog Peeth (Trust) and until the last batch of students in regular courses of studies in such manner as may be prescribed by the statutes.
49. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over period of its management under section 48 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund or the development fund. Expenditure of the University during dissolution
- (2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over period of its management, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University, by the State Government.

Enforcement of Law relating Admission & Fee 50. The law prepared by state Government relating admission & fee in the Universities and Institutes established in private sector, shall operate in this University too.

Removal of difficulties 51. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notification or order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:
Provided that no notification order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.
(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State legislature.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.